सुरक्षा उपाय और आर्थिक विकास

5.श्रीमंत शंकरादेव कलाक्षेत्र, गुवाहाटी, को स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। 8.65 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

6.गुवाहाटी में ज्योति चित्रबन (फिल्म) स्टूडियो को आधुनिक बनाया जा रहा है उसका विस्तार किया जा रहा है।

7.राज्य के आर्थिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। नूमालीगढ़ स्थित तेल शोधन कारखाने का कार्य प्रगति पर है। कथालगुड़ी में गैस आधारित विद्युत परियोजना का कार्य कार्यान्वयन अधीन है। जोगीघोपा में रेल एवं सड़क पुल के निर्माण का कार्य पूरा होने वाला है। सिलघट में एक जूट मिल को पुनः चालू किया गया है।

8.दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एक तेजपुर में और दूसरा सिलचर में, स्थापित किए गए हैं।

9.गुवाहाटी में एक आई०आई०टी० स्थापित की गई है।

अन्य मामले

10.नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार अब केवल केन्द्र सरकार के पास हैं।

11.भारत-बंगलादेश सीमा पर 2784 कि०मी० सीमा सड़कों के निर्माण और 896 कि०मी० में बाड़ लगाने की स्वीकृति दे दी गई है। इनमें से 1633.43 कि०मी० सीमा सड़क तथा 612.05 कि०मी० में बाड़ लगाने का कार्य 31.5.1996 तक पूरा कर लिया गया है।

12.आन्दोलन के संबंध में कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों की संवीक्षा की गई।

13.आन्दोलन के दौरान मारे गए व्यक्तियों के निकटतम संबंधी को अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

14.नियुक्तियों के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा उन अभ्यर्थियों के मामले में जो असम राज्य में 1.1.1980 से 15.8.1985 तक की अवधि में सामान्य तौर पर रहे हों, के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतम आयु सीमा में छह वर्ष तक की छूट देने के आदेश जारी किए गए थे।

15.आन्दोलन के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एन०एस०ए०) के अधीन निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया।

इस समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी और जब कभी आवश्यक होगा तो कार्यान्वयन के कार्य को तेज करने के लिए उपाय किए जाएंगे।

Clearance to Cogentrix Power Project in Karnataka

*29. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Cogentrix Power Project in Karnataka has been finally cleared by the Central Government;

(b) if so, what is the total cost of the project and how many MWs of power would be generated from the project; and

(c) whether environmental clearance has also been given; if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) No, Sir.

(b) The proposal of the Mangalore Thermal Power Project (4×250 MW) has been accorded techno-economic clearance of the Central Electricity Authority at a total completion cost of US$ 751.574 Million + Rs. 1580.89 crores.

(c) The project was accorded environmental clearance on 11.6.1996 stipulating various environmental measures which are required for environmental protection.

Damage to crops due to hailstorm in Andhra Pradesh

*30. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the recent hailstorm in Andhra Pradesh damaged the standing

7/1/Sec 2-B

crops worth Rs. 4 5 crores besides causing deaths of a number of people;

(b) whether in a large number of villages, mango orchards and paddy fields were damaged;

(c) if so, whether the Central Government have provided help and assistance to the people affected by the hailstorm;

(d) whether in June, 1996 heavy rains and hailstorm killed 89 people and damaged property worth crores of rupees; and

(e) if so, the help and assistance provided by the Central Government?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) to (c) According to information received from the Government of Andhra Pradesh, hailstorms during March-April, 1996 had affected agricultural and horticultural crops in an area of 35865 hectares and resulting in loss of 9 human lives. The cyclone and heavy rains of June, 1996 killed 100 people and damaged property worth Rs 129.00 crores

Under the existing scheme for financing relief expenditure, the State Government undertakes necessary relief measures using the corpus of the Calamity Relief Fund. Two instalments of Central share of Calamity Relief Fund for 1996-97 amounting to Rs. 46.57 crores have been released to the Government of Andhra Pradesh to enable the State Government to undertake necessary relief measures

कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश कम होना

*31 **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1991-92 से कृषि क्षेत्र मे सरकारी निवेश बहुत कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है; और

(ग) कृषि क्षेत्र मे सरकारी निवेश की मात्रा में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) कृषि में सकल सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश 1980-81 के मूल्यों पर 1991-92 में 1002 करोड़ रुपये, 1992-93 में 1060 करोड़ रुपये तथा 1993-94 में 1178 करोड़ रुपये था। सरकारी तौर पर लगाये गये अनुमानों के अनुसार 1994-95 में सकल निवेश थोड़ा ही कम 1095 करोड़ रुपये था। ये निवेश 1980-81 की तुलना मे बहुत कम हैं जबकि यह लगभग 1800 करोड़ रुपये था।

(ख) कृषि में निवेश मे वृद्धि की धीमी गति का मुख्य कारण उर्वरक सिंचाई और बिजली आदि पर राज सहायता में वृद्धि होना है। इससे संबंधित विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है **(नीचे देखिए)।**

(ग) आठवीं योजना (1992—97) के तहत बागवानी, मात्स्यिकी, वर्षा सिंचित खेती, लघु सिंचाई तथा फसल कटाई उपरान्त प्रबंध के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन, जैसे कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त मात्रा में निवेश किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। कृषि के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के अधीन एक नया ग्रामीण बुनियादी विकास फंड स्थापित किया गया है। तथापि, गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा कृषि में निवेश लगातार बढ़ रहा है संलग्न विवरण II में इससे संबंधित विवरण दिया गया है।

विवरण-I

कृषि पर राजसहायता का ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

मद	1980-81	1985-86	1990-91	91-92	92-93	93-94	94-95 (सं०प्रा०)	95-96 (ब,प्रा०)
उर्वरक पर राजसहायता	505	1924	4389	5185	6136	5194	5697	5900
बिजली पर राजसहायलता*	115	125	725	5938	7205	8888	*0113 (पू०वा०)	11178 (वा०यो०)